



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2017/अग्रहायण 28, 1939

No. 334]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2017/AGRAHAYANA 28, 1939

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

**जॉच शुरूआत संबंधी अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

**मामला सं. (ओ.आई.) 32/2017**

**विषय : रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम नाइट्राइट' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉच की शुरूआत**

**फा. सं. 6/29/2017-डीजीएडी.**—1. मै. दीपक नाइट्राइट (जिसे आगे आवेदक/घरेलू उद्योग/याचिकाकर्ता भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन/याचिका दायर की है जिसमें रूस (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से सोडियम नाइट्राइट (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जॉच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का

निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

### **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

3. यह आवेदन मै. दीपक नाइट्राइट लि. द्वारा दायर किया गया है। देश में सोडियम नाइट्राइट के तीन अन्य उत्पादक हैं अर्थात् पंजाब कैमिकल एंड फार्मास्युटिकल लि., नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. और राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.।

4. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, आवेदक कंपनी का उत्पादन घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अधीन योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

### **विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

5. वर्तमान जाँच के विचाराधीन उत्पाद सभी रूपों में 'सोडियम नाइट्राइट' है। यह एक अकार्बनिक रसायन है और आक्सीकारक और रीड्यूसिंग एजेंट है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका प्रयोग अधिकांशतः भेषज उद्योग, डाइ उद्योग, लुब्रिकेंट्स, निर्माण रसायन, रबड़ ब्लोविंग एजेंट, हीट ट्रांसफर साल्ट्स, मांस प्रसंस्करण, वस्त्र आदि में किया जाता है।

6. इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 28.34.10 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

### **समान वस्तु**

7. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदक ने बताया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण आदि जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं के अनुसार तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश/क्षेत्र से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना है।

### **शामिल देश**

8. वर्तमान जाँच रूस से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में है।

### **सामान्य मूल्य**

9. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की लागत और कीमतों के बारे में सूचना/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता के अभाव में, संबद्ध देश में सामान्य मूल्य का अनुमान पीओआई अवधि के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर लगाया गया है। इस अनुमान को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ सहित विधिवत रूप से समायोजित किया गया है।

### **निर्यात कीमत**

10. आवेदकों ने डीजीसीआईएस से प्राप्त आकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से औसत आयात कीमत के रूप में निर्यात कीमत को निर्धारित करने का दावा किया है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना के लिए, उन दोनों के बीच व्यापार के समान स्तर पर तुलना करना आवश्यक है। सीआईएफ स्तर पर परिकलित की गई निर्यात कीमत को समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़े और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया गया है।

**पाटन मार्जिन**

11. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत से अधिक है जिससे पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। पाटन मार्जिन के निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है।

**क्षति और कारणात्मक संबंध**

12. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों की समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति और उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्से, मालसूची में गिरावट के अनुसार परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठायी जा रही 'वास्तविक क्षति' के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

**जाँच की अवधि**

13. जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि अक्टूबर 2016 से सितम्बर 2017 (12 महीने) की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2014-15, 2015-16, 2016-17 और जाँच अवधि शामिल होगी।

**सूचना प्रस्तुत करना**

14. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें और अपने विचारों से अवगत करा सकें:

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**

**वाणिज्य विभाग,**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**

**5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जाँच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (जो प्राधिकारी की वेबसाइट ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in)) से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है।

**समय-सीमा**

16. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरूआत की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर और पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की आवश्यकता पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें।

17. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

### गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### असहयोग

25. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19<sup>th</sup> December, 2017

Case No. (O.I) 32/2017

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Sodium Nitrite" originating in or exported from Russia.**

**F. No. 6/29/2017-DGAD.**—1. M/s Deepak Nitrite Ltd (hereinafter referred to as the applicant/domestic industry/petitioner) have filed an application/petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of Sodium Nitrite (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from Russia (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, “injury” to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and “injury” exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the “injury” to the domestic industry.

#### **Domestic Industry & Standing**

3. The application has been filed by M/s Deepak Nitrite Ltd. There are three other producers of Sodium Nitrite in the Country i.e Punjab Chemical and Pharmaceuticals Ltd., National Fertilizers Ltd and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd.

4. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes “a major proportion” of the domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

#### **Product under Consideration and Like Article**

5. The product under consideration in the present investigation is “Sodium Nitrite” in all its forms. It is an inorganic chemical and is oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in pharmaceuticals industries, dye industries, lubricants, construction chemicals, rubber blowing agent, heat transfer salts, meat processing, textiles etc.

6. The product is classified under Customs Tariff heading 28.34.10 of the Customs Tariff Act. This classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the proposed present investigation.

#### **Like Article**

7. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject country and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as “like article” under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicants in India as “Like Article” to the subject goods being imported from the subject country/territory.

#### **Countries Involved**

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from Russia.

#### **Normal Value**

9. The applicant has submitted that efforts were made to get information/evidence about cost and prices of subject goods in the domestic market of the subject country. In the absence of availability of reliable information in the public domain on domestic prices of the subject goods in the subject country, the Normal value in the subject country has been estimated on the basis of cost of production of the domestic industry for POI period. The estimation has been duly adjusted including selling, general and administrative expenses and profit.

#### **Export Price**

10. The applicant has claimed determination of export price as the average import price from subject country on the basis of data procured from DGCIS. For fair comparison between the normal value and export price, it is necessary to compare the two at the same level of trade. The export prices being calculated at the CIF level, have been adjusted for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight and bank charges.

#### **Dumping Margin**

11. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price,

indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de-Minimis.

### **Injury and Causal Link**

12. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, inventories. There is sufficient prima facie evidence of the “material injury” being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

### **Period of Investigation**

13. The period of investigation for the purpose of the investigation is Oct., 2016 to Sep., 2017 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.

### **Submission of Information**

14. The known producers and exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,  
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,  
Ministry of Commerce & Industry,  
Department of Commerce,  
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -110001.

15. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form (downloadable from the website of the Authority at ([www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in))) and manner prescribed within the time limit set out below.

### **Time Limit**

16. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules. 17. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation

17. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

### **Submission of information on confidential/ Non-confidential basis**

18. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

19. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

20. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

21. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is

claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **Inspection of public file**

24. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non- confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

#### **Non-cooperation**

25. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority